अनुबंध-5

एसएलबीसी बैठकों से संबंधित कार्य-सूची

i) *वार्षिक ऋण योजना (एसीपी) तैयार करना; एसीपी के अंतर्गत कार्यनिष्पादन की निगरानी; प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिए गए ऋणों और सरकार प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए ऋण, एनपीए और वसूली (उदाहरण के लिए, योजनाबद्ध उधार में एनपीए, वसूली में आने वाली समस्याएं, आदि)।*

ii) *बैंकिंग सुविधा-रहित ग्रामीण क्षेत्रों (यूआरसी) को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करते हुए कवरेज।*

iii) *बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले बीसी संबंधी पहलू – उदाहरण के लिए, बीसी की निष्क्रियता, बीसी के परिचालन में उनके समक्ष आने वाली चुनौतियां।*

iv) *डिजिटल भुगतानों का विस्तार – उदाहरण के लिए, कनेक्टिविटी के अवसर, पीओएस मशीन जैसी भुगतान की बुनियादी संरचना की उपलब्धता, आदि।*

v) *सीडी अनुपात और एसीपी की उपलब्धि के आधार पर ज़िलों की समीक्षा करना, और ऋण उपयोग क्षमता में सुधार करने के लिए अपेक्षित उपाय – उदाहरण के लिए, ग्रामीण और कृषि बुनियादी संरचना में रहने वाले अंतराल को दूर करना।*

vi) *प्राकृतिक आपदाओं, यदि कोई हों, के मामले में ऋणों की पुनर्संरचना की समीक्षा।*

vii) *आरएसईटीआई सहित कौशल विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन – उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) आदि के साथ भागीदारी व्यवस्था करना।*

viii) *वित्तीय साक्षरता संबंधी पहलों की समीक्षा (विशेष रूप से डिजिटल वित्तीय साक्षरता) – उदाहरण के लिए, स्कूली पाठ्यक्रम में कवरेज, एफएलसी और सीएफएल की गतिविधियां, आदि।*

ix) *अतिब्याजी उधार, अति ऋणग्रस्तता, उधारकर्ता समूहों द्वारा की गई ऋण संबंधी धोखाधड़ियों, आदि से संबंधित मामले।*

x) *विभिन्न उप समितियों[1] / डीसीसी द्वारा एसएलबीसी को भेजे गए मामले।*

xi) *संचालन उप समिति द्वारा चिह्नित की गई अन्य मदें*

---

[1] कृषि, एमएसएमई और ओपीएस, वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता, डिजिटल भुगतानों से संबंधित उप समिति, जैसा कि एसएलबीसी मंच की संशोधित संरचना के अनुसार उल्लिखित।

xii) *सरकारी योजनाओं से संबंधित हाल ही की नीतिगत पहलें और इस संबंध में जागरूकता का बढ़ावा देना।*

xiii) *कोई अन्य मद।*